



यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह है कि हम यह भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं।

-मदर टेरेसा

मूल्य
₹ 3/-

सांध्य दैनिक

4PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/@4pm NEWS NETWORK)

• तर्फः 9 • अंकः 74 • पृष्ठः 8 • लखनऊ, मंगलवार, 18 अप्रैल, 2023

मप्र में ओबीसी, एससी और एसटी... | 7 | उच्च जाति और दलितों के बीच... | 3 | निकाय चुनाव में सपा-रालोद में... | 2 |

अतीक-अशरफ हत्याकांड

की होगी 'सुप्रीम' सुनवाई

- » 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत में पहुंचेगा मामला
- » यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर भी होगी बहस

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके साथ ही, यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। यह याचिका विशाल तिपारी नाम के बकाल ने दायर की है।

याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है और एक पुलिस

राज्य की ओर ले जाती है। न्यायेतर हत्याओं या फर्जी पुलिस मुद्दों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। याचिका में कहा गया है, एक लोकतांत्रिक समाज में, पुलिस को अंतिम न्याय देने या दंड देने वाली संस्था बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दंड की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है।



पुलिस का भय लोकतंत्र के लिए खतरनाक

याचिका में कहा गया है कि जब पुलिस डेयरडेविल्स बन जाती है तो कानून का पूरा शासन व्यवस्था हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उपज सेता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसके परिणामस्वरूप अधिक अपराध भी होते हैं।

न्यायिक आयोग और एसआइटी का गठन

प्रयागराज के पुलिस कमिशनर ने हत्याकांड की जांच के लिए ल्याइक आयोग के गठन के बारे सोमवार को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन किया है। डीजीपी आरके विश्वर्मा ने इस जांच दल के पर्यवेक्षण के लिए एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में भी तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। राज्य सरकार अतीक हत्याकांड को लेकर बहुत गंभीर है।

नैनी से प्रतापगढ़ जेल मेजे गए तीनों थूटर

अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों थूटरों लखनऊ विवाही, सनी सिंह और अलग मौरी को सोमवार को नैनी से प्रतापगढ़ जेल मेजे दिया है, जहाँ उन्हें अन्य बंदियों से अलग रखा गया है। डिटी जेलर और



दर्जन बरंदी रक्षक विशेष रूप से उसकी निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी से भी बैरक पर नजर रखी जा रही है। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक का बेटा अली और उसके गुर्गे बंद हैं, इसलिए तीनों थूटरों को प्रतापगढ़ मेजा गया है।

शाइस्ता कर सकती है सरेंडर!

प्रयागराज कोर्ट के बाहर की गई पुलिस की घेयबादी प्रयागराज। अतीक अशरफ हत्याकांड के बारे पुलिस और एसपीएफ की टीम ने गुरुगुलिला और शाइस्ता परिवान की तलाश तेज कर दी है। इसी बीच 50 छात्र छात्राएं की डालनी शाइस्ता के प्रयागराज कोट में सरेंडर की कथाओं ने जोरपकड़ दिया है। लालकि इस बाबत जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज कोट की घेयबादी की जा रही है, उसके द्वारा अकलों को बल मिल रहा है। क्रांति जनकारी के अनुसार प्रयागराज जिला कार्यपाली पुलिस और क्रांति शाय के जवाब सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने पूरे परिसर की घेयबादी कर रखी है। अतीक अहमद के बकालों की निगरानी एसओजी द्वारा की जा रही है।

तलाश में छापेमारी

शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की कार्रवाई की घेयबादी की घेयबादी है। प्रयागराज और शाइस्ता के द्वारा इलाकों में छापेमारी की सूचना है। जानकारी के अनुसार, लेडी डॉन की तलाश में कर्मचारियों और दिव्यादारों के घरों में घुसकर खोजवानी की जा रही है। प्रता वाला है कि चाकिया ने शाइस्ता के मायाक में भी छापा आरा गया है, जिसके बाद मायाक वाले घर छोड़कर भाग गए हैं। अतीक की पती के मायाक का घर खुला पड़ा है।

बगावत की बातें सिर्फ मीडिया का क्यास : पवार

- » मै हमेशा एनसीपी में ही हूं : अजित पवार

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकाता। राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मची उठा-पटक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार बगावत संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए इसे मीडिया की उपज बताया। ज्ञात हो महाराष्ट्र विधानसभा में विषय के नेता अजित पवार की काफी समय से एनसीपी से बगावत की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब इस मुद्दे पर शरद पवार का बयान सामने आया है।

एनसीपी प्रमुख ने अजित पवार की कथित बगावत की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अजित चुनाव संबंधी

कामों में व्यस्त हैं। यह सारी बातें सिर्फ मीडिया में हैं।

राउत के बयान को इसलिए महत्व दिया गया,

क्योंकि कुछ

समय से शरद

पवार और

अजित पवार के

बीच



मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजित भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि, अजित ने इन अटकलों को निराधार बताया। राउत ने सामना में लिखे अपने एक लेख में कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से उनकी बैठक के दौरान कहा कि कोई भी नेता दल नहीं बदलना चाहता, लेकिन जिस तरह से परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, उससे अगर कोई

पार्टी छोड़ने का निर्णय लेता

है, तो यह उसका

व्यक्तिगत मामला होगा।

एक पार्टी के रूप में

हम भाजपा के साथ

नहीं जाएंगे।

राउत ने कहा था- एनसीपी को तोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा

दरअसल, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने दबाव किया था कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन कुछ विधायक दबाव में पार्टी बदल सकते हैं। राउत ने कहा, शरद पवार ने मुझे बताया कि जिस तरह से एनसीपी को तोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए हो सकता है कुछ लोग भाजपा में शामिल हो जाएं।



बाबा साहब के सहारे की आस

भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पर मधी होड़

- » सीएम योगी, अखिलेश ने अप्रित की श्रद्धांजलि
 - » मायावती व खाबरी ने भी किया याद
 - » यूपी चुनाव में 21 प्रतिशत दलित वोट
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए दलित वोटों का अपने पाले में खीचा जाना जरूरी है। तभी यहाँ की सभी सियासी दल इस समुदाय का अपर और करने की जुगत में लगी है। सपा ने हाल ही में कांशीराम की मृत्ति का अनावरण करके अपनी मंथा जीत थी। वहीं बसपा भी इस कार बैंक में संघमारी को रोकने के लिए कार्ड कोर करसर नहीं छोड़ने के मूड़ में है। वहीं डा. भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पर सभी पार्टियों में उन्हें पुष्पांजलि देने की होड़ लगी रही।

यूपी चुनाव 2022 में दलित वोटर्स कीब 21 प्रतिशत थे पारंपरिक रूप से बीएसपी के समर्थक। लेकिन इस बार मायावती की चुप्पी और बीजेपी-सपा की सक्रियता ने समीकरण बदल दी। यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट किस ओर जाएगा? इस समय यहीं सबसे बड़ा सवाल था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनावी रेस में सबसे आगे जगह बना ली है। वहीं, बीएसपी प्रमुख मायावती अब भी ज़मीनी स्तर पर नदारद रही। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच एक आम धारणा है कि मायावती की इस असुचि के कारण उनकी पार्टी के कोर वोटर्स का एक धड़ा दूसरी ओर चला जाएगा। इस अनुमान के आधार पर दूसरे दावेदार दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लग है। दलितों ने पिछले तीन दशक में बीएसपी का समर्थन किया है। अब जिस तरह से कुछ ओबीसी नेता बीजेपी से सपा में गए हैं, उससे गैर यादव पिछड़ी जाति के वोटर्स पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस बात ने चुनाव में दलित समुदाय के वोटर्स की भूमिका बहुत बढ़ा दी थी। निकाय चुनाव में बीजेपी इस वर्ग को लुभाने के पूरे प्रयास में है। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अलावा हिंदुत्व के ज़रिए इस समाज को एक करने की कोशिश है। विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती मुख्य तौर पर जाटव उप-जाति की एकजुटता पर निर्भर करती है। दलित समुदाय में जाटव आबादी कीब 55 फीसदी है। दलित समाज पहले कांग्रेस का समर्थन था, जब तक कि 90 के दशक में कांशीराम के नेतृत्व में बीएसपी एक ताकतवर राजनीतिक शक्ति बनकर नहीं उभरी। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत ब्राह्मणों को दलितों के साथ मिलाया गया। पार्टी मेकओवर से गुजरी और मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। दलित नेताओं ने एक बार फिर उपी आजमाए और परखे हुए फॉर्मूले का सहारा लिया है। हालांकि दलितों पर मायावती के दबदबे को बीजेपी ने लगातार चुनौती दी है। बीजेपी के बल पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ही नहीं भुना रही, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं का भी सहारा ले रही है।



दलितों के घर खाना खाने का भी चलन

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के साथ दलितों को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इससे पहल घर आते-जाते और भोजन विस चुनावों में तमाम राजनीतिक दल दलित समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश की जुट थी। इसी

कड़ी में अलग-अलग राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता दलितों के घर आते-जाते और भोजन करते हुए नजर आ रहे थे। दलित नेताओं की इस वक्त पूछ भी बढ़ गई है। आखिर क्यों

दलित वोट उत्तर प्रदेश चुनावों में इतना अहम माना जाता है? क्या वाकई में दलित वोट राजनीतिक दलों के लिए सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर आंकड़ों के

मुताबिक 21 फीसदी से ज्यादा दलित मतदाता हैं, ऐसे में यह माना जा सकता है कि 5 में से 1 मतदाता, दलित समाज से आता है। इसी वजह से दलित मतदाता खासतौर पर पश्चिमी

उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। पिछले चुनावों के नतीजे भी यही बांग कर रहे हैं।

2012 में वयों 80 सीटों पर सिमटी बसपा

2012 के चुनाव में पार्टी को 25.95 फीसदी वोट मिले और 80 सीटों पर बसपा सिमट कर रह गई। लेकिन यह आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी है कि मले ही बहुजन समाज पार्टी, जिसने अपनी पहचान

यह हुआ कि मायावती की पार्टी 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन यह आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी है कि मले ही बहुजन समाज पार्टी, जिसने अपनी पहचान

बसपा की स्थापना से हुआ यूपी का भला : माया

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अम्बेडकर जयंती पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बसपा को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। मायावती ने कहा कि अति-मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान देकर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले परमपूज्य बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर शत-शत मनन व अपार शद्दा सुमन अर्पित। उनका जीवन संर्घन कराऊं

गरीबों, मजदूरों, वंचितों व अन्य महेनकारों के लिए आज भी उम्मीद की किरण। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर उनके आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के रुपे कारबां को आगे बढ़ाने तथा जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने के लिए आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की देश में स्थापना की गई,



ऐसे होता है दलित वोटों का बंटवारा

दलित वोटों का भी उपजाति के आधार पर बंटवारा हो जाता है। मसलन जाटव, पासी, वाल्मीकि, हालांकि माना यह जाता है कि इनमें से 55 फीसदी से अधिक वोट जाटव बिहारी से आते हैं और यह जाटव बिहारी कीब 21.8 फीसदी वोट निले थे। वहीं बसपा को इन चुनावों में 22.2 फीसदी के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं।

तो वहां पर मायावती की पार्टी भले ही 19 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन वो वोट प्रतिशत में अपने से ज्यादा सीट लासिल करने वाली था से आगे ही थी। सपा को जल्द 2017 के विधानसभा चुनावों में करीब 21.8 फीसदी वोट निले थे। वहीं बसपा को इन चुनावों में 22.2 फीसदी के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं।

सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

याचिकार्ता बोले हमें मी शादी का अधिकार मिले, केंद्र बोला- आर से दक्षिण तक राय लेनी होगी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रबूद्ध, जस्टिस एसके कॉल, जस्टिस एस रवीन्द्र भट, जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस हिमा कोहली की पांच जजों की

संवैधानिक बोंच सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी कर रहे हैं।

सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा ऐसा नहीं है, जिस पर एक पक्ष में बैठे 5 लोग, दूसरे पक्ष में बैठे 5 लोग और बीच पर बैठे 5 विद्वान बहस कर सकें। इसमें दक्षिण भारत के किसान और उत्तर भारत के बिजनेसमैन का भी नजरिया जानना होगा। हम अभी भी इन याचिकाओं के आधार पर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस मामले पर सभी राज्य एकराय न हों। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पर कोर्ट खुद फैसला ले सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानना चाहते हैं कि

याचिकार्ता क्या दलीलें दे रहे हैं। देखते हैं कि याचिकार्ता और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। सॉलिसिटर जनरल हमें नहीं बता सकते कि यह फैसला कैसे करना है। हम सही बक्ता पर आपको भी सुनेंगे।

वहीं विरिष्ट वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम अपने घरों में प्राइवेसी चाहते हैं। साथ ही यह भी कि हमें सार्वजनिक जगहों पर कोई लांचन ना सहना पड़े। हम चाहते हैं कि 2 लोगों के लिए शादी और परिवार को लेकर वैसी ही व्यवस्था हो, जैसी अभी दूसरों के लिए चल रही है। शादी और परिवार की हमारे समाज में इज्जत होती है। कानून में से इस मामले पर आपराधिक और अप्राकृतिक हिस्सा हट गया है। ऐसे

में हमारे अधिकार भी समान हैं। हम सेम सेक्स वाले लोग हैं। हमें भी समाज के हेट्रोसेक्शुअल ग्रुप के तौर पर संविधान के तहत समान अधिकार मिले हैं। आपने ही यह फैसला किया है।

हमारे समान अधिकारों के रास्ते में केवल एक ही रुकावट थी 377। हम बढ़े होते जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि

कर्नाटक आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 25 अप्रैल तक टाला

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। कर्नाटक सरकार ने स्थगन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के सरकार के आदेश के आधार पर कोई नई नियुक्तिया प्रवेश नहीं किया जाएगा।

शादी की सम्मान हो। आज स्थिति क्या है? ये जो लोग हैं, इन्हें गे कहा जाता है, छाँका कहा जाता है। अगर ये कहीं जाते हैं तो लोग इन्हें देखने लगते हैं। आर्टिकल-21 के तहत यह अधिकारों पर प्रतिबंध और उनका उल्लंघन है। आपने ही अनुज गर्ग के केस में सेक्स की परिभाषा को माना है, जिसमें कहा गया था कि सेक्स के मायने यौन इच्छा से है ना कि किसी के पुरुष या महिला होने से।

विश्व धरोहर दिवस पर छात्रों को दी जानकारी

» महाराजा बिजली पासी
राजकीय महाविद्यालय
में हुआ कार्यक्रम

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय, आशियाना लखनऊ में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ सुमन गुप्ता के निर्देशन पर इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ सनोबर हैदर के द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी साझी विरासत को संजोने एवं रक्षा करने ही और उनमुख किया गया।

इस अवसर पर प्लेसेज आफ



रिलिजियस एंड कल्चरल टूरिज्म इन डिस्ट्रीट आफ यूपी पर विशेष चर्चा की गई। इसमें वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, अयोध्या एवं प्रयागराज जैसे जनपदों में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु छात्र छात्रों को प्रेजेटेशन दिखा कर जागरूक किया।

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता को दी जमानत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग (ऑनलाइन माध्यम के जरिये लोगों से धन जुटाना) के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने गोखले को राहत देते हुए कहा कि मामले में अरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। पीठ ने कहा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का जोरदार विरोध किया।

हालांकि, आरोप की प्रकृति पर गैर करते हुए और चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं, हम जमानत प्रदान कर रहे हैं। पीठ ने कहा, याचिकार्ता को अहमदाबाद शहर, साइबर अपराध थाना में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में निचली अदालत की ओर से तय जमानत राशि और मुचलका भरने के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

जो चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते वो गाड़ियों के काफिले में घूम रहे: वरुण

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पीलीभीत। सांसद वरुण गांधी दो दिन पहले ही दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान ललौरीखेड़ा विकास खंड क्षेत्र में आयोजित जनसभा में दिए गए संबोधन का गीड़ियों इंटररेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। जिसमें सांसद वरुण गांधी ने बैरें नाम लिए जनपद के एक माननीय पर निशाना साधा है।

सांसद ने कहा कि हमें 35 साल हो गए, हमारे पास कोई घर है? क्या कोई जमीन है? हमने कोई कालोनी काटी है? हम तो आज भी एक कमरे में रहते हैं। हमारी जगह कोई और होता तो बड़ा महल बना चुका होता। बगीचा बना देता। वरुण ने

कहा कि जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वे पांच-पांच गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। जो पहले कहते थे, भर्खिया हमें एक मौका दे दो। हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे। इन लोगों ने पीलीभीत शहर का आधा हिस्सा घेर लिया है। सांसद अपने संबोधन में तीखे हमले करते हुए बार बार उपस्थित लोगों से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वे सही कह रहे हैं? जिसके जबाब में उपस्थित लोग हाँ कह रहे हैं। सांसद वरुण गांधी ने संबोधन में किसी का नाम तो नहीं लिया है। लेकिन जिले के एक माननीय से इसी सीधी तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है।

भीषण आग

गोमती नगर स्थित पत्रकारापुरम के एक कैफे में आज सुबह आग लग गयी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।



मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिये केंद्र और राज्य सरकार में कशर हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

हस्ताक्षर

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक बहिता चतुर्वेदी के लिए 4पीएम आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रधान संपादक - अर्चना दयाल, संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार:

संदीप बंसल, कार्टनिस्ट: हसन जदी, दूरभाष: 0522-4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजीय, सं-SSP/LW/NP-495/2018-2020

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरडी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होगे।

आधुनिक तकनीक और आपकी सोच से भी बड़े आश्वर्यजनक उपकरण

चाहे टीवी खराब हो या कैमरे, गाड़ी में जीपीएस की जरूरत हो या बच्चों की और घर की सुरक्षा।



सिवयोग डॉक्टरेस ब्रावोली
संपर्क 9682222020, 9670790790